आवश्यक

संख्या-110/2021/2515/26-3-2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर,
देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया,
गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 24 सितम्बर, 2021

विषयः शासनादेश दिनांक 15.07.2020 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पीआईएल संख्या-1859/2020 नायक जनसेवा संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में दिनांक 13.08.2021 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-273/26-3-2020 दिनांक 15.07.2020 (संलग्नक-1) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोंड की पर्याय/उपजाति नायक एवं ओझा को उक्त जनपदों में नियमानुसार जाचोंपरान्त अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके प्रस्तर-3 में यह उल्लेख किया गया है कि "भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 में उत्तर प्रदेश के कतिपय 13 जनपदों यथा महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में गोंड व उसकी पर्याय/उपजाति यथा धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के उक्त कतिपय 13 जनपदों में पाये जाने वाले गोंड व उसकी पर्याय/उपजाति नायक व ओझा नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र है"।

2- उक्त के शासनादेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पीआईएल संख्या-1859/2020 नायक जन सेवा संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में दिनांक 13.08.2021 को मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश (संलग्नक-2) के कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः-

In view of the aforesaid, the State Government was not required or was having competence to issue order either giving interpretation or substitution of the Notification. The order dated 15th July, 2020 shows reference of the caste and the district as per the Gazette Notification of Government of India but at the end of Para 3 of the impugned order, apart from the caste referred in the middle part of Para 3, further refers to the caste Gond or its synonyms / sub-caste Nayak and Ojha to fall in the category of scheduled tribes. The aforesaid was not permissible. In fact, the Government of U.P. should follow the Gazette Notification issued of the Government of India. In any case, the impugned order was issued to stop fraudulent act of persons in obtaining caste certificate. Thus, we may not have interfered in the order but looking to certain substitution in Para 3, it is set aside. However, with the clarity that while issuing caste

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

certificate in favour of reserve caste candidate named in the Gazette Notification, the State of U.P. would be at liberty to make proper scrutiny of the application so that caste certificate may not be taken fraudulently.
With the aforesaid clarification, the writ petition is allowed.

3- भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने स्पष्टीकरण आदेश संख्या-12016/26/2001-टीए(आरएल) दिनांक 15.12.2003 (संलग्नक-3) में यह उल्लेख किया गया है कि "Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Rajgond has been added as synonym to Gond tribe in the districts of Mahajajganj, Sidharthanagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Ajamgarh, Jaunpur, Balia, Gajipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra district and they have not been specified as separate entries in the list of Scheduled Tribes of Uttar Pradesh".

4- अतएव मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार की अधिसूचना अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 (संलग्नक-4) में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक-6 पर अंकित गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड, जो 13 जनपदों (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र) में सूचीबद्ध है तथा भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-12016/26/2001-टीए(आरएल) दिनांक 15.12.2003 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप जनपद के नायक व ओझा समुदाय के आवेदनकर्ताओं द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत 1356फ0, 1359फ0 को तहसील के मूल रिकार्ड से मिलान किये जाने के पश्चात सही पाये जाने पर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। आवेदनकर्ता के भूमिहीन होने की दशा में उसके कुटुम्ब/परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षिक संस्थाओं/विद्यालय की टी.सी., नजदीकी निर्विवादित परिवारों से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल कर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5- यदि किसी भी स्तर पर गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आता है तो शासन द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय समिति (जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी) के समक्ष प्रस्तुत करें, उसे निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-110/2021/2515(1)/26-3-2021-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अध्यक्ष, राजस्व परिषद उ0प्र0, आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0।

2-मण्डलायुक्त, बस्ती/गोरखपुर/आजमगढ़/वाराणसी/मिर्जापुर मण्डल।

3-निदेशक, समाज कल्याण/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

आवश्यक

संख्या- 273 / 26-3-2020

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर,
देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया,
गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक जून, 2020

विषय: जनपद के गोंड की पर्याय/उपजाति नायक एवं ओझा को जांचोपरान्त अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2930/26-3-2007-3(7)/03, दिनांक-22.08.2007 एवं शासनादेश संख्या-518सीएम/26-3-2009 दिनांक 31.08.2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोरखपुर व महराजगंज जनपद के नायक जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेशों की गलत व्याख्या करके सामान्य वर्ग के नायक (ब्राम्हण) जाति व अन्य पिछडी जाति में सम्मिलित नायक जाति के व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के ओझा (ब्राम्हण) जाति के व्यक्तियों द्वारा भी फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने की शिकायतें प्राप्त हुई है।

3- यहां उल्लेखनीय है कि भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम-2002 में उत्तर प्रदेश के कतिपय 13 जनपदों यथा-महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र में गोंड व उसकी पर्याय/उपजाति यथा धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के उक्त कतिपय 13 जनपदों में पाये जाने वाले गोंड व उसकी पर्याय/उपजाति नायक व ओझा नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र है।

4- उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या-2930/ 26-3-2007-3(7)/03, दिनांक-22.08.2007 एवं शासनादेश संख्या-518सीएम/ 26-3-2009 दिनांक 31.08.2009 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समुचित परीक्षण/जांच पड़ताल कराकर अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर गोंड की पर्याय/उपजाति यथा नायक एवं ओझा जाति के व्यक्तियों को ही नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0सं0 273 (1)/26-3-2020-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद उ0प्र0, आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0।
2- मण्डलायुक्त, बस्ती/गोरखपुर/आजमगढ़/वाराणसी/मिर्जापुर मण्डल।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-2

**Court No. - 29**
**Case :-** PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 1859 of 2020
**Petitioner :-** Nayak Jan Seva Sansthan
**Respondent :-** State Of U.P. And 2 Others
**Counsel for Petitioner :-** Krishna Mohan Misra
**Counsel for Respondent :-** C.S.C.

**Hon'ble Munishwar Nath Bhandari,Acting Chief Justice**
**Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.**

Heard learned counsel for the petitioner and learned Standing counsel for the State.

This writ petition has been filed to challenge the order dated 15.07.2020 issued by the Additional Chief Secretary, Samaj Kalyan Anubhag-3, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

Learned counsel for the petitioner submits that competence to issue notification to identify the caste to fall to scheduled tribes lies with Parliament under Article 342 of the Constitution of India. A Notification was published in the Gazette on 08.01.2003 to declare certain caste to fall in the category of scheduled tribes for the State of U.P. The Notification aforesaid named the caste to fall in the category of scheduled tribes in the district of Maharajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jaunpur, Ballia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra. After the Notification aforesaid, the State Government issued an order on 15th July, 2020 in reference to the same caste and the district to fall in the category of scheduled tribes though the authority does not lie for it more so when there is substitution of the caste.

Coming to the impugned order dated 15th July, 2020, it is submitted that while naming the castes for 13 districts given in the Notification, para 3 of the impugned order further refers to the caste of Gond and their synonyms or sub-caste Nayak and

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Ojha to be scheduled tribes. The aforesaid was not in the domain of the State Government rather they cannot tinker or substitute the Notification published in the Gazette under Article 342 of the Constitution of India.

The learned Senior Counsel, Sri Krishna Mohan Mishra has made a reference of the judgement of Apex Court in the case of **State of Maharashtra vs. Milind and others (2001) 1 Supreme Court Cases** 4 where it was held that the State Government have no authority to even make interpretation of the Notification. The prayer is accordingly to set aside the order dated 15th July, 2020.

Learned Additional Advocate General, Sri Manish Goyal submits that the order impugned herein is in consonance to the Gazette Notification dated 08.01.2003. The necessity to issue the impugned order was due to the malpractices adopted by the person to take caste certificate fraudulently. It is despite the person not falling in one of the caste referred in the Gazette Notification published by the Government of India. After taking caste certificate fraudulently, they were using it for different purpose. Thus, to void aforesaid, the order dated 15th July, 2020 was issued. The aforesaid has wrongly been taken as an order either for interpretation or substitution of the Gazette Notification of Government of India. In any case, if this Court give direction to issue caste certificate in reference to the Gazette Notification dated 08.01.2003, State would have no objection but it may be made clear that the caste certificate may be issued after scrutiny so that those not following in any of the caste given in the Notification may not get the certificate. The prayer is accordingly to allow the State Government to make proper scrutiny of the application before issuance of caste certificate.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

We have considered the rival submissions of parties and perused the record. It is not in-dispute that competence to issue Notification for caste to fall in the category of scheduled tribes lies with the Parliament under Article 342 of the Constitution of India. The Gazette Notification was issued on 08.01.2003 to notify certain caste to be scheduled tribes for 13 districts of the State of U.P.

In view of the aforesaid, the State Government was not required or was having competence to issue order either giving interpretation or substitution of the Notification. The order dated 15th July, 2020 shows reference of the caste and the district as per the Gazette Notification of Government of India but at the end of Para 3 of the impugned order, apart from the caste referred in the middle part of Para 3, further refers to the caste Gond or its synonyms / sub-caste Nayak and Ojha to fall in the category of scheduled tribes. The aforesaid was not permissible. In fact, the Government of U.P. should follow the Gazette Notification issued of the Government of India. In any case, the impugned order was issued to stop fraudulent act of persons in obtaining caste certificate. Thus, we may not have interfered in the order but looking to certain substitution in Para 3, it is set aside. However, with the clarity that while issuing caste certificate in favour of reserve caste candidate named in the Gazette Notification, the State of U.P. would be at liberty to make proper scrutiny of the application so that caste certificate may not be taken fraudulently.

With the aforesaid clarification, the writ petition is allowed.

Order Date :- 13.8.2021 / Manoj

(Rajendra Kumar-IV, J.) (Munishwar Nath Bhandari, A.C.J.)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-3

No.12016/26/2001-TA(RL)
Govt. of India
Ministry of Tribal Affairs

Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Dated 15.12.2003

To

Shri Chandra Prakash
IAS
Social Welfare Division
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

Subject: Clarification regarding specification of Nayak, Ojha, Dhuria added in the list of Scheduled Tribes of Uttar Pradesh vide Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002

Sir,

With reference to your d.o. letter No.3648/26-3-2003/3/7/2003 dated 14th October 2003 on the above mentioned subject and to say that vide Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 (copy enclosed) Dhuria, Nayak, Ojha, Pahari, Rajgond has been added as synonym to Gond tribe in the districts of Maharajganj, Siddharthnagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Ajamgarh, Jaunpur, Ballia, Ghazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra districts and they have not been specified as separate entries in the list of Scheduled Tribes of Uttar Pradesh.

Yours faithfully,

(Dr R.C Mahapatra)
Deputy Director

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-4

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/2003 REGISTERED NO. DL-33004/2003

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2003/पौष 18, 1924
No. 10] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2003/PAUSA 18, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

*New Delhi, the 8th January, 2003/Pausa 8, 1924 (Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 7th January, 2003 and is hereby published for general information:—

# THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 2002

No. 10 OF 2003

*[7th January, 2003]*

An Act to provide for the inclusion in the lists of Scheduled Tribes, of certain tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities, equivalent names or synonyms of such tribes or communities, removal of area restrictions and bifurcation and clubbing of entries; imposition of area restriction in respect of certain castes in the lists of Scheduled Castes, and the exclusion of certain castes and tribes from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in relation to the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal:

Be it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002. Short title.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(*n*) in PART XVI.—*West Bengal*, after entry 38, insert—

"39. Limbu (Subba)

40. Tamang";

(*o*) in PART XVII.—*Mizoram*, after entry 14, insert "15. Paite";

(*p*) in PART XVIII.—*Arunachal Pradesh*,—

(*i*) in entry 8, at the end, insert ", Idu, Taroan";

(*ii*) after entry 12, insert—

"13. Hrusso

14. Tagin

15. Khamba

16. Adi.";

(*q*) in PART XIX.—*Goa*, after entry 5, insert—

"6. Kunbi

7. Gawda

8. Velip.";

(*r*) in PART XXII.—*Jharkhand*,—

(*i*) in entry 1, at the end, insert ", Agaria";

(*ii*) in entry 15, at the end, insert ", Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia";

(*iii*) in entry 18, at the end, insert ", Nagesia";

(*iv*) in entry 19, at the end, insert ", Mudi-Kora";

(*v*) in entry 23, at the end, insert ", Kumarbhag Paharia";

(*vi*) in entry 24, at the end, insert ", Patar";

(*vii*) in entry 25, at the end, insert ", Dhangar (Oraon)";

(*viii*) after entry 30, insert—

"31. Kawar

32. Kol.".

(2) In the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, after entry 5, insert—

"6. Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Raj Gond (in the districts of Mahrajganj, Siddarth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jaunpur, Ballia, Ghazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra)

7. Kharwar, Khairwar (in the districts of Deoria, Ballia, Ghazipur, Varanasi and Sonbhadra)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।